खाद्य सुरक्षा योजना में एक करोड़ पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने राजसमंद में 491 करोड़ रूपए की 347 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया

राजसमंद, 02 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को राजसमंद के भिक्षु निलयम में आयोजित समारोह में 491 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के 347 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिनमें 369 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 266 कार्यों का लोकार्पण तथा 122 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 81 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं से श्रीनाथजी की आस्था एवं महाराणा प्रताप के शौर्य धरा पर विकास गाथा में एक नया अध्याय जुडेगा।

इस अवसर पर कुंभलगढ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़, राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड, जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, पूर्व उप जिला प्रमुख सोहनी देवी, पूर्व प्रधान अरविन्द सिंह राठौड सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बडी संख्या में आमजन मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण एवं दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दे रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को राजसमंद के भिक्षु निलयम में आयोजित समारोह में 491 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के 347 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विशेष योग्यजनों को इलेक्ट्रॉनिक मोटराइज़्ड ट्राई साइकिल वितरित कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करते हुए शिक्षा से लेकर रोजगार की राह प्रशस्त की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से स्वस्थ राजस्थान का संकल्प साकार हो रहा है। मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा के लिए 4 लाख 82 हजार से अधिक कूपन जारी किए गए हैं। जरूरतमंदों को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में 1 करोड पात्र व्यक्तियों के नए नाम जोड़े हैं।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजसमंद के भिक्षु निलयम में आयोजित समारोह में विशेष योग्यजनों को इलैक्ट्रॉनिक मोटराइज़्ड ट्राई साइकिल, पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के चैक, 167 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के चैक दिए।**

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजनों को इलेक्ट्रॉनिक मोटराइज़्ड ट्राई साइकिल पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के चेक राजीविका 167 स्वयं सहायता समूहों को 7.90 करोड रुपये के क्रेडिट लिंकेज के चेक एवं कोविड-19 में अनाथ आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरित किये।

गोवा में कांग्रेस ने चुनावी गठबंधन पर वार्ता शुरु की

पणजी, 02 अगस्त। गोवा में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों, कांग्रेस और 'गोवा फॉरवर्ड पार्टी' (जीएफपी) ने गठबंधन को लेकर शुरुआती बातचीत शुरू कर दी है। इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) ने भी विपक्षी एकजुटता के तहत साथ आने के संकेत दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, बातचीत में गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडणकर ने रविवार को बताया कि उन्होंने गठबंधन बनाने को लेकर गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई के साथ चर्चा की है।

चोडणकर ने कहा कि शनिवार को हुई बातचीत केवल शुरुआती दौर की थी और पुराने गठबंधन को दोबारा आगे बढ़ाने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान, आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष वाल्मीकि नायक ने भी शनिवार को समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन पर निर्णय लेने के लिए गठित पार्टी समिति के साथ बैठक की।

हरमाड़ा पुलिस ने सरकारी भूमि पर उगाया 40 किलो गांजा जब्त किया

जयपुर, 02 अगस्त। हरमाड़ा पुलिस ने ग्राम बिचपड़ी में खाली आबादी भूमि पर उगाई जा रही अवैध गांजे की फसल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 48 हरे-गीले गांजे के पौधे जब्त किए, जिनका शुद्ध वजन 40 किलो 384 ग्राम निकला। मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश गुप्ता, सहायक पुलिस आयुक्त चौमूं अंजू यादव तथा हरमाड़ा थानाधिकारी नरेन्द्र भड़ाना के निर्देशन में गठित विशेष टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बिचपड़ी स्थित जगदीश मंदिर के पास खाली पड़ी आबादी भूमि पर संदिग्ध पौधे उगाए गए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि सभी 48 पौधे गांजे के हैं। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन खेती करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी। राजस्व रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि उक्त जमीन गांव की सार्वजनिक खाली आबादी भूमि है। इसके बाद पुलिस ने सभी पौधों को उखाड़कर जब्त कर लिया।

- **अभी तक खेती करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है।**

प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की खेती किसी सुनियोजित नेटवर्क द्वारा अवैध तस्करी और क्षेत्र में नशे का जाल फैलाने के उद्देश्य से की जा रही थी।

'जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

छोटा मुद्दा है और रुचिका का बयान एक बड़ी समस्या है।''

उन्होंने कहा, ''हम आज भी जवाब मांग रहे हैं। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर पैलैट गन क्यों चलाई गई? सुरक्षा बलों को पैलैट गन क्यों दी गई? कीलों से जड़ी लाठियां क्यों इस्तेमाल की गईं, जिनसे प्रदर्शनकारी घायल हुए?''

नेहा ने यह भी सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नेताओं द्वारा कही गई अपमानजनक बातों की उसी तरह जांच क्यों नहीं हुई।उन्होंने कहा, ''जब आपके लोग संसद से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जब आरएसएस का कोई विचारक कहता है कि ''जंतर मंतर पर रेप पसंद करने वाली महिलाएं प्रदर्शन कर रही थीं, तब क्या वह आपको अभद्र नहीं लगता?''

नेहा ने आरोप लगाया कि विवाद के बाद उन्हें और रुचिका सिंह को सोशल मीडिया पर कई बलात्कार की धमकियां मिलीं।

उन्होंने कहा, ''यह दमन महिलाओं को निशाना बनाकर किया जा रहा है। रुचिका के खिलाफ छह एफआईआर दर्ज की गई हैं, उन्हें बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। प्रदर्शनकारियों पर की गई इस कार्रवाई में जैंडर का पहलू साफ नज़र आता है।''

उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन्हें जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, ''समाज में पहले से मौजूद जाति, धर्म और जैंडर के विभाजन को अब दमन की प्रक्रिया में भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आंदोलन की एकता को तोड़ा जा सके।''

यह कहते हुए कि आंदोलन का मकसद हर प्रदर्शनकारी की हर बात को सही ठहराना नहीं है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें पूरे आंदोलन को सिर्फ भाषा पर बहस तक सीमित करने की कोशिश पर आपत्ति है।

उन्होंने कहा, ''देश के सामने मुद्दा यह नहीं है कि किसी ने कोई बुरा शब्द बोला या नहीं। असली मुद्दा यह है कि क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे आम नागरिकों पर पैलैट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों के लिए यही बात परेशान करने वाली होना चाहिए।''

जहां पेपर लीक विरोधी प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि 20 जुलाई को शांतिपूर्ण संसद मार्च के दौरान पुलिस ने उन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और पैलैट गन का इस्तेमाल किया, वहीं दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि सुरक्षा बलों ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की

इस सप्ताह की शुरुआत में रुचिका सिंह के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें नोएडा में दर्ज की गई एक ज़ीरो एफआईआर भी शामिल है, जिसे जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया है। नेहा ने कहा कि युवाओं को डराने और उन्हें भयभीत करने के लिए एफआईआर दर्ज की जा रही हैं।

ये मामले भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं जो जानबूझकर अपमान करने, लोक शांति भंग करने वाले बयान देने और मानहानि से संबंधित हैं। उन्होंने कहा, ''पूरी जिम्मेदारी अमित शाह की है। पूरी जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त की है। अगर किसी को इस्तीफा देना चाहिए या हटाया जाना चाहिए तो यही दो लोग हैं। किसी छोटे अधिकारी को निलंबित कर देना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है।''20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पैलैट गन और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों पर सवाल उठाते हुए सीपीआई (एमएल) लिबरेशन से संबद्ध वामपंथी छात्र संगठन की प्रमुख ने कहा कि सरकार यह बताने में विफल रही कि सुरक्षा बलों को पैलैट गन और ''कीलों से जड़ी लाठियां'' क्यों दी गईं। उन्होंने कहा, ''हम आज भी जवाब मांग रहे हैं। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर पैलैट गन क्यों चलाई गई? सुरक्षा बलों को पैलैट गन क्यों दी गई? कीलों से जड़ी लाठियां क्यों इस्तेमाल की गईं, जिनसे प्रदर्शनकारी घायल हुए?''

नेहा बोरा ने कहा कि चाहे यह कथित कार्रवाई किसी मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई हो या वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री की ही बनती है। उन्होंने कहा, ''अगर यह मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुआ, तो आप किस तरह के गृह मंत्री हैं? और अगर यह आपके आदेश पर हुआ, तो आप कैसा आपराधिक शासन चला रहे हैं, जहां आम नागरिकों पर पैलैट गन चलाई जा सकती हैं?''

बोरा ने कहा कि पुलिस की कथित कार्रवाई के बाद आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब यह केवल पेपर लीक का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए व्यवहार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक अभियान बन गया।

ए.आई.एस.ए. की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ''हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे पास आते थे और कहते थे कि वे अब तक भाजपा सरकार को वोट देते रहे हैं, लेकिन आज उनके वोट की वजह से ही हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। वो लोग कह रहे थे कि उनके वोट की वजह से छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और अब उन्हें बहुत शर्म आ रही है।''उन्होंने कहा, ''यह आंदोलन अब केवल धर्मेंद्र प्रधान के बारे में नहीं है। यह इस बात के बारे में है कि क्या सरकार देश के आम नागरिकों के साथ इतनी बर्बरता कर सकती है।'' उन्होंने दावा किया कि छात्रों और युवाओं के भीतर पैदा हुई विश्वासघात की भावना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर केंद्रित हो गई है। उन्होंने दोहराया कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग और आंदोलन के दौरान या उसके बाद हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से बाढ़ आई

श्रीनगर, 02 अगस्त। मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले के सफापोरा इलाके में रविवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई जिससे घर, दुकानें, बाग और सड़कें पानी में डूब गईं और भारी अव्यवस्था फैल गई।

जानकारी के अनुसार पानी का अचानक बहाव कई घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घुस गया जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा और इलाके में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। कई बाग भी पानी में डूब गए जिससे बागवानों को अपनी फसलों के भारी नुकसान की आशंका है।

अचानक आई बाढ़ के कारण कई सड़कें और अंदरूनी गलियां जलमग्न हो गईं जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार दिन की शुरुआत में हुई भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने जैसी घटना के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए जिससे स्थानीय नालों और जल निकासी चैनलों में पानी का स्तर तेज़ी से बढ़ गया।

- **घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाग, सड़कें पानी में डूबी, फसलों को भारी नुकसान।**

अधिकारियों ने बताया कि सफापोरा में अचानक आई बाढ़ के कारण पानी का स्तर तेज़ी से बढ़ ा जिससे कई घर डूब गए और लोगों में दहशत फैल गई। इस अचानक आई बाढ़ ने कई रिहायशी इलाकों को प्रभावित किया। घरों में पानी घुसने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ कई आवासीय घरों में घुस गई और क्षेत्र में खड़ी फसलों के अलावा बड़े कृषि क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचाया। सफापोरा की यह घटना जम्मू और कश्मीर में सक्रिय मानसून के व्यापक दौर के बीच हुई है।

अमरनाथ यात्रा फिर शुरु

जम्मू, 02 अगस्त। भारी बारिश के कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा मौसम में सुधार होने के बाद जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रविवार को फिलहाल बहाल कर दी गई है बारिश और मलबा जमा होने के कारण बंद हुए 250 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) को मरम्मत के बाद यातायात के लिए खोल दिया गया है।

यात्रियों का नया जत्था कड़े सुरक्षा पहरे और एस्कॉर्ट गाड़ियों के साथ बेस कैंप से रवाना किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने पंजीकरण और टोकन वितरण से जुड़ी ऑफलाइन सेवाएं भगवती नगर बेस कैंप में स्थानांतरित कर दी हैं।

इससे पहले भूस्खलन प्रभावित हिस्सों की मरम्मत के लिए उधमपुर और बनिहाल के बीच एनएच-44 को बंद करने के बाद शनिवार को तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई थी। मरम्मत के बाद शनिवार शाम हाइवे को फिर से खोल दिया गया।

आरटीआई कार्यकर्ता ने अभिजीत दीपके के खिलाफ शिकायतें कीं

नई दिल्ली, 02 अगस्त। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके एक बार फिर विवादों में हैं। गुजरात के सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने उनके परिवार की संपत्ति, पार्टी की फंडिंग और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर तीन अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से शिकायत की है। तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है।

अमित तिवारी का कहना है कि अभिजीत दीपके के पिता भगवानराव दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) में जूनियर इंजीनियर (जेई) के पद पर कार्यरत थे। उनका दावा है कि इस पद पर औसतन 60 से 65 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी आय में परिवार ने अपने बच्चों को अमेरिका जैसे महंगे देश में पढ़ ाई के लिए कैसे भेजा। तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि भगवानराव दीपके और उनके परिवार की आय और संपत्ति की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

- **सूरत के कार्यकर्ता अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग तथा सीबीआई से कार्यवाही की मांग की।**

अमित तिवारी ने चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि कॉकरोच जनता पार्टी खुद को राजनीतिक संगठन के रूप में पेश कर रही है और लोगों से चंदा भी जुटा रही है।

तिवारी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि यह जांच की जाए कि क्या सीजेपी बिना पंजीकरण के राजनीतिक गतिविधियां चला रही है और यदि ऐसा है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

हमने हमला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है और ना ही होर्मुज़ पर उनके देश का स्टैंड बदला है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने ईरानी वार्ताकारों के करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए रविवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब तक अमेरिका उनकी जमीन पर हमले जारी रखेगा, तब तक तेहरान रणनीतिक जलमार्ग होर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोलेगा। अमेरिका होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खुलवाना चाहता है तो उसे सैन्य हमले रोकने होंगे। दोनों देशों की ओर से ये बयान ऐसे समय आए हैं, जब बीते दिनों में क्षेत्र में शांति की किरण दिखी है।ईरान में अमेरिका कीकरीब दो हफ्ते से जारी बमबारी के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान पर हमले रोकने का ऐलान किया है। इसके बाद से अमेरिका या ईरान की ओर से किसी नए हमले की खबर नहीं मिली है।

कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार आज, 18 को मंत्री पद मिलेगा

बेंगलुरु/नई दिल्ली, 02 अगस्त। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल का विस्तार सोमवार यानि 3 अगस्त को किया जा सकता है। इससे पहले नई दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने अंतिम दौर की बैठक कर नए मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया है। पिछले सप्ताह से नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच लगातार बैठकें हुईं। इन बैठकों में क्षेत्रीय, जातीय, सामुदायिक और लैंगिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के नामों पर चर्चा की गई।

सूत्रों के मुताबिक, इस विस्तार में करीब 18 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। मुस्लिम समुदाय, महिलाओं, अंहिदा वर्ग और युवा विधायकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने पर विशेष जोर है। साथ ही डी के शिवकुमार और सिद्धारमैया समर्थक विधायकों के बीच भी संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। बैठकों में नए नामों में रिजवान अर्शद, कनीज फातिमा और तनवीर सैत जैसे नेताओं के नामों पर चर्चा हुई। वहीं डी के शिवकुमार लक्ष्मी हेब्बालकर को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बी जेड जमीर और शरथ बाचे गौड़ा जैसे नामों पर भी विचार हुआ। इसी सप्ताह कर्नाटक भवन में सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार की अलग से बैठक हुई थी, जिसके बाद दोनों नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद के साथ खड़गे के आवास पर पार्टी नेतृत्व से चर्चा की थी।

- **मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की खड़गे, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, सुरजेवाला व सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद नाम फाइनल हुए**

हनीट्रैप में फंसाकर सीकर के कारोबारी से 1 करोड़ रू. मांगे

पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ अवैध वसूली, ब्लैकमेलिंग और अपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया

जयपुर, 02 अगस्त। राजधानी जयपुर में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीकर निवासी 60 वर्षीय कारोबारी ने एक महिला, उसके पति और एक सहयोगी पर हनीट्रैप में फंसाकर 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर जयपुर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अवैध वसूली, ब्लैकमेलिंग और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पीड़ित कारोबारी फाइनेंस का व्यवसाय करते हैं। वर्ष 2025 में उनकी मुलाकात एक परिचित के माध्यम से आरोपी महिला और उसके पति से हुई थी। महिला ने स्वयं को विदेश में नौकरी दिलाने वाली फर्म संचालित करने वाली बताया। सितंबर 2025 में उसने विदेश भेजने के नाम पर युवकों से लिए गए पैसे खर्च हो जाने और अपने खिलाफ दर्ज मामले का हवाला देकर कारोबारी से आर्थिक मदद मांगी। उसने संपत्ति गिरवी रखकर ऋण लेने का भरोसा दिलाया, जिस पर कारोबारी ने अक्टूबर 2025 में 6.50 लाख रुपये दिए। इसके बदले महिला ने उन्हें एक चेक सौंपा। शिकायत के अनुसार अप्रैल 2026 में महिला ने कारोबारी को यह कहकर होटल बुलाया कि फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि आने वाले हैं और उनकी गारंटी से उसका ऋण स्वीकृत हो जाएगा। चौबीस अप्रैल को होटल पहुंचने पर महिला ने अपने कार्ड से भुगतान नहीं होने का बहाना बनाकर कारोबारी के क्रेडिट कार्ड से बिल जमा कराया। आरोप है कि महिला उन्हें कमरे में ले गई, जहां उसने शराब पिलाई। कारोबारी का आरोप है कि नशे की हालत में महिला ने उनके साथ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं और बाद में इन्हीं तस्वीरों के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में महिला ने 1 लाख रुपये मांगे, पैसे नहीं देने पर तस्वीरें परिवार और बेटे को भेजने की धमकी दी। इसके बाद जून 2026 में महिला ने कारोबारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। कारोबारी का आरोप है कि महिला के एक परिचित ने फोन और व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर कहा कि गिरफ्तारी से बचना है तो 1 करोड़ रुपये देकर समझौता करना होगा। जब कारोबारी ने पहले दिए गए 6.50 लाख रुपये लौटाने की बात कही तो आरोपियों ने कथित रूप से रकम भूल जाने और नया भुगतान करने का दबाव बनाया।

- **आरोप है कि महिला ने होटल में बुलाकर, शराब पिलाकर, आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेलिंग शुरु की**

बारामूला में आतंकी सहयोगी पकड़ा गया

बारामूला, 02 अगस्त। जम्मू-कश्मीर के बारामूला में रविवार को सुरक्षाबलों ने ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू अर्थात आतंकी सहयोगी) को दबोच लिया। उसके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि नरवाव के जंडफरान-गोरीवान क्रॉसिंग पर 46 राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस एसओजी, 53 बटालियन सीआरपीएफ और 112 बटालियन बीएसएफ के जवानों ने संयुक्त नाका लगाया था।गोरीवान की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति ने नाका देखकर भागने की कोशिश की, जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर सुरक्षाबलों को उसके पास से एक कैमोफ्लाज़्ड एमपी-5 टाइप पिस्तौल, 10 ज़िंदा 9एमएम कारतूस वाली एक मैगज़ीन, एक मोबाइल फोन और एक काला बैकपैक मिला।

शेख हसीना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घटना शेख हसीना के 15 साल के शासन के खत्म होने की दूसरी बरसी के मौके पर हो रही है, जब 5 अगस्त 2024 को विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन एक देशव्यापी सरकार-विरोधी आंदोलन में बदल गया था।

भारत के क्लीन एनर्जी उत्पादन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कचरे के प्रबंधन पर भी बना रहेगा।

परमाणु बिजलीघरों के सामान्य संचालन और रखरखाव के दौरान रेडियोधर्मी कचरा पैदा होता है।

इसमें इस्तेमाल किए गए फिल्टर, सुरक्षा कपड़े, औजार, उपकरण और वो अन्य सामग्री शामिल होती हैं जो रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में आई हों।

जब किसी परमाणु रिएक्टर की आयु पूरी हो जाती है और उसे हटाया जाता है, जिसे डीकमीशनिंग कहते हैं, तब भी रेडियोएक्टिव कचरा पैदा होता है।एक आम गलतफहमी यह है कि सारे रेडियोएक्टिव कचरे में समान स्तर की रेडियोएक्टिविटी होती है।

वास्तव में, अलग-अलग प्रकार के कचरे में रेडियोएक्टिविटी का स्तर अलग-अलग होता है। इसलिए उनके रखरखाव, उपचार और निपटान के तरीके भी अलग होते हैं। जिन पदार्थों में अधिक रेडियो एक्टिविटी होती है, उनके लिए अधिक कड़े नियम और लंबे समय तक निगरानी की आवश्यकता होती है।

संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, परमाणु बिजलीघरों से निकलने वाला रेडियोएक्टिव कचरा मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है- गैस, लिक्विड और सॉलिड। स्वाभाविक रूप से, इन तीनों का निपटान अलग-अलग तरीके से किया जाता है।

भारत रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन कैसे करता है?

सरकार ने कहा कि रेडियोएक्टिव कचरा बनने के तुरंत बाद उसका निपटान नहीं किया जाता है।

पहले उसके भौतिक स्वरूप और उसमें मौजूद रेडियो एक्टिविटी के स्तर के अनुसार उसका ट्रीटमैंट किया जाता है। उसके बाद ही उसके निपटान पर विचार किया जाता है।

गैस वाले कचरे को, रैगुलेटरी सीमाओं के अनुसार, छोड़ने से पहले स्रोत पर ही ट्रीट किया जाता है। जबकि, तरल कचरे को उसकी विशेषताओं के आधार पर, स्थापित शुद्धिकरण विधियों का उपयोग करके ट्रीट किया जाता है। ठोस कचरे को अलग-अलग किया जाता है और उसका आकार कम करने के बाद उसका निपटान किया जाता है।

संसद में दिए गए जवाब में यह भी कहा गया कि सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी प्रकार का रेडियोएक्टिव कचरा तब तक पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता, जब तक उसे रैगुलेटरी कंट्रोल से मंजूरी न मिल जाए, या उसे नियमों से छूट न दी जाए अथवा उसे रैगुलेटरी कंट्रोल से बाहर न माना जाए।

रेडियोएक्टिव कचरा पैदा करने वाली हर इकाई को एईआरबी से अनुमति लेनी होती है। यह अनुमति तय करती है कि कितनी मात्रा में रेडियोएक्टिव पदार्थ छोड़ा जा सकता है और किस स्वीकृत तरीके से उसका निपटान किया जाएगा।

ठोस रेडियोएक्टिव कचरे का निपटान विशेष रूप से बनाई गई सुविधाओं में किया जाता है, जैसे पत्थर की लाइनिंग वाली खाइयाँ, रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट की खाइयाँ और टाइल वाले गड्ढे। ये सभी एक्सैस कंट्रोल्ड क्षेत्रों में होते हैं।

इन संरचनाओं में बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कई प्राकृतिक और कृत्रिम सुरक्षा परतें होती हैं। इनका उद्देश्य रेडियोएक्टिव पदार्थ को आसपास के वातावरण में फैलने से रोकना है।

इसके अलावा, इन निपटान स्थलों की लगातार निगरानी की जाती है। इसमें आसपास बने बोर-वैल की निगरानी भी शामिल है।

तथापि, भारत अब उस समस्या का सामना करना शुरू कर रहा है, जिसका सामना कई अन्य देश लंबे समय से कर रहे हैं।

अलग-अलग देश अपने परमाणु कार्यक्रम के आकार, वे किस प्रकार के फ्यूल चक्र का पालन करते हैं, और अपनी दीर्घकालिक कचरा प्रबंधन नीतियों के आधार पर रेडियोधर्मी कचरे का अलग-अलग तरीके से प्रबंधन करते हैं।

भारत, अमेरिका और फिनलैंड, तीनों ही कड़े नियमों और कई सुरक्षा परतों पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस्तेमाल किए जा चुके परमाणु ईंधन के प्रबंधन के मामले में इनकी नीतियां अलग हैं। इस्तेमाल हो चुका परमाणु ईंधन अत्यधिक रेडियोएक्टिव ईंधन होता है।

भारत एक बंद परमाणु ईंधन चक्र (क्लोज़्ड न्यूक्लियर फ्यूल सायकल) की नीति अपनाता है। इसके तहत इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को केवल कचरा नहीं माना जाता। पहले इसे रैगुलेटरी निगरानी में सुरक्षित रखा जाता है, और फिर यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसी दोबारा उपयोग में आने वाली सामग्री को निकालने के लिए रीप्रोसैस किया जाता है।

इस प्रक्रिया के बाद बचा हुआ उच्च स्तर का रेडियोएक्टिव कचरा ही लंबे समय तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए रीप्रोसैसिंग भारत की दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

नशे से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री ने परिवारों से अपील की कि यदि घर का कोई बच्चा नशे का शिकार हो जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण इसे छिपाया न जाए। बच्चों के साथ संवाद की संस्कृति विकसित करना जरूरी है, ताकि समय रहते उनके व्यवहार में आने वाले बदलावों को पहचाना जा सके।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्